योजना का सार

कौशल भारत मिशन : परिवर्तन का एक दशक

संदर्भ

- वर्ष 2015 में शुरू किया गया कौशल भारत मिशन एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है, जिसने लाखों युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से लैस किया है।
- यह कौशल अंतर को पाटने, कार्यबल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, उद्योग की ज़रूरतों और वैश्विक रुझानों के साथ जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वैश्विक कौशल केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मज़बूत होती है।

एक मज़बूत कौशल ढाँचा तैयार करना

सुव्यवस्थित कौशल प्रशासन

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने 20 से अधिक खंडित कार्यक्रमों को एकीकृत किया, जिससे कौशल के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण तैयार हुआ।
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) ने भारत के कार्यबल को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाए रखने के लिए एक स्केलेबल और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की।

शिक्षा के साथ कौशल का एकीकरण

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCF) 2023 व्यावसायिक प्रशिक्षण को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करता है।

- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे के साथ संरेखित योग्यताओं के लिए क्रेडिट स्थानांतरण, आई.टी.आई. स्नातकों के लिए शैक्षणिक समकक्षता और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सीखने व रोज़गार के बीच सहज संक्रमण की सुविधा प्रदान करने के साथ ही भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का समर्थन करते हैं।

उद्योग संपर्क और प्रशिक्षुता को मज़बूत करना

- 100 से अधिक उद्योग परामर्शों ने प्रशिक्षण को बाज़ार की ज़रूरतों के साथ जोड़ा है।
- आई.टी.आई. में फ्लेक्सी और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली वास्तविक दुनिया के संपर्क को बढ़ाती है।
- फ्लेक्सी एम.ओ.यू का तात्पर्य लचीले समझौता ज्ञापन योजना से है, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के भारत में प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। यह योजना उद्योगों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के साथ साझेदारी करने की अनुमति देती है, ताकि वे अपनी विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम बना सकें।
- संशोधित राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना के माध्यम से 42 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया है।
- त्वरित रोज़गार विकास कार्यक्रम उच्च मांग वाले क्षेत्रों में तेज़ी से कौशल विकास को लक्षित करता है।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल कौशल को अपनाना

- स्किल इंडिया डिजिटल हब ए.आर/वी.आर सामग्री और एआई-संचालित करियर मैपिंग के साथ किसी भी समय सीखने में सक्षम बनाता है।
- डिजिटल कौशल कार्ड सत्यापन योग्य प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं, जिससे पोर्टेबिलिटी और मान्यता बढ़ती है।

अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और वैश्विक मान्यता

- स्किल इंडिया वैश्विक प्रतिभा अंतराल को संबोधित कर रहा है, जिसमें 16 देशों में 3.7 मिलियन रोज़गार अवसरों की पहचान की गई है।
- जापान, जर्मनी, इज़रायल और यू.ए.ई के साथ द्विपक्षीय समझौते, साथ ही 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC) कार्यबल की गतिशीलता को बढ़ावा दे रहे हैं।
- भारत वर्ष 2024 में वर्ल्ड स्किल्स में 13वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2011 में यह 39वें स्थान पर था।

AI मिशन और भविष्य का कौशल

- राष्ट्रीय AI मिशन के साथ संरेखित, स्किल इंडिया डिजिटल हब ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में AI-आधारित शिक्षा को एकीकृत करता है।
- Google, NVIDIA और Microsoft के साथ सहयोग स्वास्थ्य सेवा व वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में AI कौशल का विस्तार कर रहा है।

बजट सहायता और बुनियादी ढाँचा विस्तार

- केंद्रीय बजट 2024-25 में स्किल इंडिया के लिए ₹8,800 करोड़ आवंटित किए गए थे।
- योजनाओं में हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत 1,000 आई.टी.आई. को अपग्रेड करना और कौशल विकास के लिए पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

नवीन कौशल वित्तपोषण मॉडल

- कौशल ऋण, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड और कौशल वाउचर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तक पहुँच व मांग-संचालित कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं।
- एकीकृत डिजिटल ढाँचा योजना अभिसरण को आगे बढ़ा रहा है।

पारंपरिक और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना

- पीएम विश्वकर्मा प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के साथ 18 पारंपरिक व्यवसायों को पुनर्जीवित कर रहा है।
- पीएम-जनमन और वन धन योजना जैसी योजनाएँ ग्रामीण और आदिवासी रोज़गार को बढ़ावा देती हैं।
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत आई.टी.आई. विरासत शिल्प को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कौशल अंतराल को पाटना और डाटा उपयोग को बढ़ाना

- निर्बाध शैक्षणिक-कौशल संक्रमण के लिए एन.एस.क्यू.एफ. पाठ्यक्रमों को स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जा रहा है।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय क्षेत्रीय कौशल अंतर अध्ययन कर रहा है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में कौशल संबंधी डाटा शामिल करने के लिए काम कर रहा है।

निष्कर्ष

- विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, वर्ष 2030 तक कुशल प्रतिभाओं की कमी के कारण 85 मिलियन से अधिक नौकरियाँ खाली रह सकती हैं, जबकि स्वचालन और एआई-संचालित प्रौद्योगिकियाँ उद्योगों को नया स्वरूप प्रदान करेंगी। एकीकृत नीति, उद्योग सहयोग और तकनीक-संचालित पहलों के साथ, भारत वैश्विक कौशल राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

विकसित भारत के लिए डिजिटल मार्ग

संदर्भ

- भारत, जो लंबे समय से सॉफ्टवेयर में अपने वैश्विक नेतृत्व के लिए जाना जाता है, अब हार्डवेयर विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है।

- निर्माणाधीन पाँच सेमीकंडक्टर संयंत्रों के साथ, देश जल्द ही अपना पहला मेक-इन-इंडिया चिप लॉन्च करने के लिए तैयार है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही भारत के शीर्ष तीन निर्यातों में से एक बन गया है।

बुनियादी ढाँचे और नवाचार के माध्यम से ए.आई का लोकतंत्रीकरण

- भारत एक अद्वितीय ढाँचे के माध्यम से सभी के लिए ए.आई को सुलभ बना रहा है:
- **कंप्यूट पावर :** शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए सब्सिडी दरों (घ्100/घंटा से कम) पर 18,000+ GPU के साथ एक सामान्य कंप्यूट सुविधा उपलब्ध है।
- **डाटा उपलब्धता :** AI मॉडल को प्रशिक्षित करने, पूर्वाग्रह को कम करने और सटीकता में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर, गैर-व्यक्तिगत अनाम डाटासेट विकसित किए जा रहे हैं।
- **आधारभूत मॉडल :** भारत राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने स्वयं के बड़े भाषा मॉडल (LLM) और डोमेन-विशिष्ट AI समाधान बना रहा है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)% एक वैश्विक मॉडल

- सार्वजनिक धन और निजी नवाचार के साथ निर्मित भारत के DPI दृष्टिकोण में आधार, UPI और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- शासन और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अब DPI को AI के साथ जोड़ा जा रहा है।
- UPI को जापान द्वारा पेटेंट दिए जाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। G-20 शिखर सम्मेलन में, कई देशों ने भारत के DPI मॉडल को अपनाने में रुचि व्यक्त की।

महाकुंभ 2025 का तकनीक-संचालित प्रबंधन

- दुनिया की सबसे बड़ी मानव सभा का प्रबंधन भारत की DPI और AI क्षमताओं का उपयोग करके किया गया-
- रियल-टाइम AI उपकरणों ने रेलवे भीड़ के प्रवाह की निगरानी की।
- चैटबॉट में एकीकृत भाषिनी ने बहुभाषी सहायता, खोया-पाया केंद्र सहायता और आवाज़-आधारित सहायता प्रदान की।

भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण

- भारत हर हफ्ते एक वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) का निर्माण कर रहा है। इसके लिए सरकार निम्न कदम उठा रही है-
- AI, 5G और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को अपडेट करना।
- शिक्षा को तकनीकी रुझानों के साथ संरेखित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करना।

व्यावहारिक ए.आई विनियमन

- भारत द्वारा ए.आई विनियमन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं-
- **संतुलित दृष्टिकोण :** न तो अत्यधिक प्रतिबंधात्मक और न ही पूरी तरह से बाज़ार-संचालित।
- **तकनीकी-कानूनी रणनीति :** केवल कानूनों के बजाय तकनीकी सुरक्षा उपायों पर बल।
- **अनुसंधान सहायता :** डीपफेक से निपटने, गोपनीयता बढ़ाने और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संस्थानों में ए.आई परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।

लोगों पर केंद्रित परिवर्तन

- इसके मूल में, भारत की डिजिटल और ए.आई क्रांति अपने लोगों को सशक्त बनाने के संबंध में है जिसका उद्देश्य मज़बूत, सुलभ बुनियादी ढाँचे और प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से नवाचार के साथ ही समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।